आकाशवाणी केन्द्र शिमला
16.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता– राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।

- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विजिलेंस को आर.टी.आई. के दायरे से बाहर करने के सुक्खू सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।

- राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी ने पठानकोट–मंडी फोरलेन के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने का केंद्र सरकार से किया आग्रह।

- प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट– किसान–बागवान खुश।

- प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन।

एमओयू

प्रदेश में डेयरी उत्पाद क्षेत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आज शिमला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हुए इन समझौता ज्ञापनों के तहत कांगड़ा ज़िला के ढगवार में सितंबर माह तक मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट का कार्य पूरा किया जाएगा और इसका संचालन पूरी तरह से एन.डी.डी.बी. करेगा। इसके अलावा नाहन व नालागढ़ में डेयरी प्लांट जबकि जलाड़ी व झलेड़ा में चिलिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि दूध खरीद पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने घर–द्वार के समीप सम्मानजनक रोज़गार प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर और मज़बूत सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊना ज़िला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से बनने वाली समनाल–पूबोवाल सड़क के निर्माण कार्य के भूमि पूजन के बाद उन्होंने ये बात कही। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क के सुदृढ़ीकरण से औद्योगिक गतिविधियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के लोगों को बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सतर्कता विभाग एंटी करप्शन ब्यूरो को आर.टी. आई के कानूनी दायरे से बाहर करने फैसले को लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से लाया गया मुख्यमंत्री का ये फैसला कानूनी तौर पर सही कैसे हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस फैसले के पीछे की मंशा को भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स में की गई भारी बढ़ौतरी पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे बिना सोचे–समझे लिया गया एक अदूरदर्शी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार करों के माध्यम से राजस्व जुटाने की कोशिश में प्रदेशवासियों के साथ अन्याय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को अपने जनविरोधी निर्णयों पर पुनः विचार करने की सलाह दी है।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के सृजन व विस्तार के लिए 23 दलहन प्रसंस्करण इकाईयों को मंजूरी दी गई हैं, जिनमें से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2026–27 रबी खरीद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने नेफेड और एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से पहले ही डेढ़ लाख दलहन उत्पादक किसानों को पंजीकृत कर लिया है।

इंदु गोस्वामी

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वमी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से पठानकोट–मंडी फोरलेन के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने का आग्रह किया है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ये मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण कार्य पूरा होने से पठानकोट–मंडी के बीच की दूरी एक सौ 71 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरा होने से कांगड़ा, चंबा, पालमपुर, डलहौजी और मंडी के पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि रजोल से ठांणपुरी खंड की डीपीआर तैयार करने की प्रकिया अंतिम चरण में है।

मौसम

पश्चिमी विक्षोभ की सकियता के चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक–रूक कर बर्फबारी का क्रम जारी रहा। मार्च के महीने में हुई इस वर्षा व बर्फबारी से तापमान में ज़ोरदार गिरावट आई है। जनजातीय ज़िला लाहौल–स्पिति के ताबो में आज न्यूनतम तापमान माईनस 2 दशमलव 5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अटल टनल के साऊथ पोर्टल के पास फंसे पर्यटकों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उधर चंबा ज़िला में हुई ताज़ा बर्फबारी से जोत–चुवाड़ी मार्ग,

खजियार–डलहौज़ी व चंबा–भांदल–लंगेरा सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हैं। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर बाद ओलावृष्टि व वर्षा हुई है। प्रदेश के किसान और बागवान इस बर्फबारी और वर्षा को फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि व वर्षा जबकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

पैंशनर

हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति अपनी लंबित देनदारियों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में पैंशनरों के विभिन्न संगठनों ने आज शिमला में प्रदर्शन किया। पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि 21 मार्च को पेश होने वाले बजट में यदि उनकी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो 30 मार्च को प्रदेशभर से आए पैंशनर विधानसभा का घेराव करेंगे।

बिंदल

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर वन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सिरमौर ज़िला के शिलाई में सामने आए अवैध पेड़ कटान मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और पार्टी प्रवक्ता बलदेव तोमर ने आज नाहन में कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर लीपा पोती करने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, तो भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।